



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 14, 2009/पौष 24, 1930

No. 19]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 14, 2009/PAUSA 24, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जाँच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2009

विषय : चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सोडियम नाइट्राइट के आयातों के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जाँच की शुरुआत।

सं. 17/1/2008-डीजीएडी.—मैसर्स दीपक नाइट्राइट लिमिटेड ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (समय-समय पर यथासंशोधित तथा जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) एवं सीमाशुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रति संतुलनकारी शुल्क का आकलन संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (समय-समय पर यथासंशोधित तथा जिन्हें एतदपश्चात् सीवीडी नियमावली कहा गया है) के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध देश/चीन जन.गण. कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सोडियम नाइट्राइट (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) पर सब्सिडीकरण का आरोप लगाते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है और संबद्ध वस्तु पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क अधिरोपित करने के लिए प्रति संतुलनकारी शुल्क जाँच की शुरुआत करने का अनुरोध किया है।

2. और यतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने की दृष्टि से चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु से संबंधित सब्सिडियों, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और सब्सिडियों एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान हैं, अतः प्राधिकारी उपर्युक्त नियमावली के नियम 6 के अनुसरण में कथित सब्सिडियों की मौजूदगी, सीमा तथा प्रभाव का निर्धारण करने तथा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की वह राशि संस्तुत करने, जिसे यदि अधिरोपित किया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, के उद्देश्य से, कथित सब्सिडीकरण एवं इससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बारे में एतद्वारा जाँच की शुरुआत करते हैं।

3. घरेलू उद्योग

यह आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से मैसर्स दीपक नाइट्राइट लिमिटेड ने प्रस्तुत किया है। आवेदक ने क्षति के संबंध में सूचना प्रदान की है। रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार याचिकाकर्ता का उत्पादन भारतीय उत्पादन के 50% से अधिक होने के कारण कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख अनुपात बनता है। इस प्रकार याचिकाकर्ता उपर्युक्त नियमावली के नियम 2(ख) एवं नियम 6(3) की अपेक्षाओं

को पूरा करता है। मैसर्स दीपक नाइट्राइट लिमिटेड को उपर्युक्त नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर "घरेलू उद्योग" माना जा रहा है।

4. विचाराधीन उत्पाद

वर्तमान जाँच में शामिल उत्पाद सोडियम नाइट्राइट है। सोडियम नाइट्राइट एक आक्सीकारक अभिकर्ता होने के साथ एक अवकारक अभिकर्मक भी है। यह एक सफेद खेदार पूर्ण होता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से भेषज उद्योगों, रंजक उद्योगों, स्नेहकों, निर्माण रसायनों, रबड़ ब्लोइंग एजेंट, उष्मा अंतरण लवणों, मांस प्रसंस्करण, वस्त्रोद्योग आदि में किया जाता है। सोडियम नाइट्राइट के उत्पादन हेतु प्रमुख कच्चा माल अमोनिया है, जिसे एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च तापमान पर नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तत्पश्चात् सोडियम नाइट्राइट प्राप्त करने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड को कास्टिक सोडा द्वारा अवशोषित किया जाता है। सोडियम नाइट्राइट का उपयोग मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के मध्यवर्ती पदार्थों के उत्पादन हेतु रंजक उद्योगों द्वारा और एनाल्जिन, थियोफाइलीन एवं कैफीन आदि के उत्पादन हेतु भेषज उद्योग द्वारा किया जाता है।

सोडियम नाइट्राइट को इस अधिनियम की अनुसूची 1 के सीमाशुल्क उपशीर्ष 2834.00 तथा आइटीसी के 28341010 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

5. समान वस्तुएँ

याचिकाकर्ता न दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु चीन जन.गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तु के समान वस्तु है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और चीन जन.गण. से निर्यातित वस्तु के बीच कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं है। याचिकाकर्ता का दावा है कि दोनों वस्तुएँ तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से परस्पर प्रतिस्थापनीय हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को चीन जन.गण. से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

6. शामिल देश

वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध देश भी कहा गया है) है।

7. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

याचिकाकर्ता ने नियमावली के अनुबंध-I के अंतर्गत यथानिर्धारित तरीके से, घरेलू उद्योग को हुई "क्षति" से संबंधित विभिन्न मानदण्डों के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद घरेलू उद्योग को क्षति का लगातार सामना करना पड़ा है। सूचना के मूल्यांकन से ज्ञात होता है कि आयातों की मात्रा निरपेक्ष रूप में और भारत में उत्पादन

तथा खपत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक है। आयातों के कारण घरेलू उद्योग कीमतों में कटौती का सामना कर रहा है। प्रदत्त सूचना के आधार पर यह देखा जा सकता है कि चीन जन. गण. द्वारा कथित सस्तिडीकरण एवं संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण लाभ, निवेश से आय, नकद लाभ एवं मालसूचियों के रूप में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में गिरावट आई है।

इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है कि नियमावली के अनुसरण में प्रति संतुलनकारी शुल्क जांच की शुरुआत को युक्तियुक्त ठहराने की दृष्टि से चीन जन. गण. से सस्तिडी प्राप्त आयातों के कारण भी घरेलू उद्योग को “क्षति” हुई है।

8. जांच अवधि

वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 है। तथापि क्षति की जांच की अवधि में अप्रैल, 2004-मार्च, 2005; अप्रैल, 2005-मार्च, 2006; अप्रैल, 2006-मार्च, 2007 की अवधियाँ एवं जांच की अवधि (पीओआई) को शामिल किया जाएगा।

9. सस्तिडियाँ

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि सोडियम नाइट्राइट के उत्पादक चीन जन.गण. द्वारा दी जा रही प्रति-उपलब्ध सस्तिडियों से लाभान्वित हुए हैं; और कतिपय स्कीमों/कार्यक्रमों की मौजूदगी दर्शाने वाला साक्ष्य प्रस्तुत किया है और जाँच शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए दावा किया है कि ये प्रति-उपलब्ध सस्तिडियाँ हैं। निम्नलिखित स्कीमों/कार्यक्रम जांच के दायरे में शामिल हैं, जिनके बारे में आरोप है कि इनके माध्यम से चीन जन.गण. ने सोडियम नाइट्राइट के उत्पादकों/निर्यातकों को प्रति-उपलब्ध सस्तिडियाँ प्रदान की हैं :-

(I) अनुदान/ऋण तथा इक्विटी प्रविष्टि जैसी निधियों के प्रत्यक्ष अन्तरण द्वारा

(क) अनुदान कार्यक्रम:

1. राज्य प्रमुख प्रौद्योगिकी नवीकरण परियोजना निधि
2. चीन जन.गण. की सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर/प्रांतीय स्तर पर राज्य के स्वामित्व वाले घाटे में जा रहे उद्यमों को अनुदान

ख. अधिमानी ऋण प्रदाय:

1. सरकारी नीति के अंतर्गत ऋण प्रदाय कार्यक्रम
2. पूर्वोत्तर पुनरुज्जीवन कार्यक्रम से संबंधित ऋण एवं ब्याज सस्तिडियाँ
3. लायोनिंग प्रान्त के पंचवर्षीय कार्यवाहों के अनुसरण में प्रदत्त ऋण

(III) राजस्व अधित्याग अथवा जो अन्यथा देय था, का संग्रहण नहीं किया गया। उदाहरणार्थ कर ऋण जैसे राजकोषीय प्रोत्साहन

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा शुरू किए गए आयकर कार्यक्रम:

1. विदेशी निवेशित उद्यमों हेतु अधिमानी कर नीतियां - दो मुक्त तीन अर्द्ध कार्यक्रम
2. निर्यातोन्मुख एफआईई हेतु आयकर छूट
3. एफआईई हेतु अवस्थिति के आधार पर आयकर दरों में कमी
4. निर्यातोन्मुख उद्यमों में एफआईई मुनाफे के पुनर्निवेश हेतु निगमित आयकर वापसी कार्यक्रम
5. नए अथवा उच्च प्रौद्योगिकी उद्यमों हेतु आयकर दर में कमी
6. एफआईई में अनुसंधान एवं विकास हेतु अधिमानी कर नीतियां
7. घरेलू तौर पर उत्पादित उपकरणों की खरीद पर आयकर ऋण - घरेलू स्वामित्व की कम्पनियों पर लागू
8. घरेलू तौर पर उत्पादित उपकरणों की खरीद पर आयकर ऋण - एफआईई पर लागू

घ. प्रान्तीय सरकारों द्वारा अपनाए गए आयकर कार्यक्रम

5. केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवर्तित अप्रत्यक्ष कर कार्यक्रम एवं आयात टैरिफ कार्यक्रम

1. निर्यातों पर वैट में छूट
2. घरेलू तौर पर उत्पादित उपकरणों की एफआईई द्वारा खरीद पर वैट रियायत
3. प्रोत्साहित उद्योगों हेतु आयातित प्रौद्योगिकी एवं उपकरणों पर वैट तथा टैरिफ छूट

(IV) सामान्य अवसंरचना से इतर वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रावधान

1. पर्याप्त से कम आय हेतु बिजली, प्राकृतिक गैस, पानी तथा उपयोगी सेवाओं का प्रावधान
2. पर्याप्त से कम आय हेतु भूमि का प्रावधान

चीन जन.गण. की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली में दिनांक 19 नवम्बर, 2008 को जांच-पूर्व परामर्श किया गया था। परामर्श के दौरान चीन सरकार ने दावा किया कि जाँच अवधि के दौरान अनेक स्कीमें/कार्यक्रम विद्यमान ही नहीं थे अथवा वापस ले लिए गए/संशोधित कर दिए गए थे। तथापि चीन सरकार ने यह सिद्ध नहीं किया है कि जांच अवधि के दौरान न्यूनतम से कम सीमा तक कोई प्रति-उपलब्ध सब्सिडी नहीं थी।

चीन सरकार के दावे रिकॉर्ड में दर्ज कर लिए गए हैं और जाँच के दौरान इन पर आगे विचार किया जाएगा। नियमावली के अनुसरण में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की शुरुआत को युक्तियुक्त सिद्ध करने की दृष्टि से प्रति-उपलब्ध सब्सिडियों की मौजूदगी के बारे में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

10. निर्यात कीमत

याचिकाकर्ता ने आईबीआईएस द्वारा प्रदत्त सौदेवार आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है। नियमावली के अनुसरण में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की शुरुआत को युक्तियुक्त सिद्ध करने की दृष्टि से निर्यात कीमत के बारे में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं।

11. सब्सिडी मार्जिन

याचिकाकर्ता ने विभिन्न स्कीमों में सब्सिडी की मार्जिन का अनुमान लगाया है और दावा किया है कि चीन के उत्पादक कथित स्कीमों के कारण न्यूनतम से अधिक सीमा तक लाभान्वित हुए हैं।

12. चीन जन. गण. से वस्तुओं का पाटन

पहले से सिद्ध किए गए वस्तुओं के पाटन को देखते हुए चीन जन. गण. से आयातों के मामले में संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है। मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा का अनुरोध करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा अलग से प्रस्तुत एक याचिका के आधार पर प्राधिकारी ने दिनांक 17 नवम्बर, 2008 की अधिसूचना सं. 15/24/2008-डीजीएडी द्वारा एक मध्यावधि समीक्षा जांच अलग से शुरू की थी।

13. प्रक्रिया एवं सूचना प्रस्तुत करना

जांच की कार्यवाई के दौरान प्राधिकारी यह निर्धारण करेंगे कि क्या सम्बद्ध देश में उद्गमित संबंधित उत्पाद सब्सिडी प्राप्त तथा प्रति-उपलब्ध है और क्या इस सब्सिडीकरण से भारतीय घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

सब्सिडी एवं प्रति संतुलनकारी उपाय करार के अनुच्छेद 13.2 के अनुसरण में जांच की अवधि के दौरान, वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने एवं पारस्परिक रूप से सहमत समाधान निकालने के उद्देश्य से चीन जन. गण. की सरकार को परामर्श जारी रखने का समुचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से उनकी सरकार भारत में ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं को निर्धारित तरीकों से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने एवं अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत कराने के लिए उन्हें अलग से पत्र भेजे गए हैं। वर्तमान जांच में भाग लेने का इच्छुक अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी निम्नलिखित सकता है :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
कमरा नं. 240, उद्योग भवन
नई दिल्ली-110107

197 GI/08-2

14. समय सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित में इस प्रकार भिजवाई जानी चाहिए जो प्राधिकारी को उपर्युक्त पते पर इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों (40 दिनों) से अनधिक अवधि के भीतर प्राप्त हो जाए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो प्राधिकारी उपर्युक्त नियमावली के अनुसरण में रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

15. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना :

पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अनुसरण में हितबद्ध पक्षकारों से प्राधिकारी को प्रदत्त किसी भी गोपनीय सूचना का अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। अगोपनीय पाठ अथवा गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश पर्याप्त रूप से विस्तृत होना चाहिए और इससे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सार्थक जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार की राय में यदि इस सूचना का सारांश नहीं बनाया जा सकता, तो उसके कारणों का विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

16. असहयोग

नियम 7(8) के अनुसार ऐसे मामले में जहां कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना समुचित अवधि के भीतर उपलब्ध कराने से मना करता है अथवा अन्यथा प्रस्तुत नहीं करता अथवा जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

17. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसरण में कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2009

Subject : Initiation of Countervailing Duty investigation concerning imports of Sodium Nitrite originating in or exported from People's Republic of China.

No. 17/1/2008-DGAD.—M/s. Deepak Nitrite Limited has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act 1975, (as amended from time to time and hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (as amended from time to time and hereinafter referred to as the CVD Rules) alleging subsidization of Sodium Nitrite (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from

People's Republic of China (hereinafter referred to as the subject country/China PR) and requested for initiation of countervailing duty investigation for levy of countervailing duties on the subject goods.

2. And whereas, the Authority finds that sufficient evidence of existence of subsidies in relation to subject goods originating in or exported from China PR, injury to the domestic industry and causal link between the subsidies and injury exist to justify initiation of a countervailing duty investigation, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged subsidisation and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 6 of the said Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged subsidies and to recommend the amount of countervailing duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

3. Domestic Industry

The Application has been filed by M/s Deepak Nitrite Limited on behalf of the domestic industry. The applicant has provided injury information. As per the evidence available on record, production of the petitioner, being more than 50% of Indian production, accounts for a major proportion of the total domestic production. The petition thus satisfies the requirements of Rule 2(b) and Rule 6(3) of the Rules. M/s. Deepak Nitrite Limited is being treated as "domestic industry" within the meaning of Rule 2(b) supra.

4. Product under consideration

The product involved in the present investigation is Sodium Nitrite. Sodium Nitrite is an oxidizing as well as a reducing agent also. It is a white crystalline powder mostly used in pharmaceuticals industries, dye industries, lubricants, construction chemicals, rubber blowing agent, heat transfer salts, meat processing, textiles, etc. Major raw material for production of Sodium Nitrite is ammonia, which is converted into nitrous oxide at high temperature in presence of catalyst. The nitrous oxide is then absorbed in caustic soda to get Sodium Nitrite. Sodium Nitrite is primarily used in dyes industries for producing various types of intermediates, pharmaceuticals industry for production of analgin, theophylline, caffeine etc.

Sodium Nitrite is classified under custom sub-heading 2834.00 of Schedule 1 of the Act, and within 28341010 of the ITC. The classification is, however, indicative and in no way binding on the scope of the present investigations.

5. Like Articles

The petitioner has claimed that the goods produced by the domestic industry are like articles to the goods originating in or exported from China PR. It has been stated that there is no significant difference in the subject goods produced by the petitioner and those exported from China PR. Petitioner claims that the two are technically and commercially substitutable. For the purpose of present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as like articles of the subject goods imported from China PR.

6. Countries involved

The country involved in the present investigation is People's Republic of China (also referred to as China PR).

7. Period of investigation

The period of investigation for the purpose of present investigation is **1st April, 2007 to 31st March, 2008**. However, the injury investigation period will cover the periods April 2004-March 2005, April 2005-March 2006, April 2006-March 2007, and the Period of Investigation (POI).

8. Subsidies

The petitioner has alleged that producers of Sodium Nitrite have benefited from countervailable subsidies maintained by China PR and provided evidence showing existence of certain schemes/program claiming that the same constitute countervailable subsidies to justify initiation of an investigation. The following schemes/ program alleged in the petition to have provided countervailable subsidies to the producers/exporters of Sodium Nitrite in China PR are included in the scope of investigation:

- (I) By direct transfer of funds such as grants/loans and equity infusion
 - A. Grant Programs:
 - 1. State Key Technology Renovation Project Fund
 - 2. Grants to Loss-Making State-Owned Enterprises by the Government of China PR at the National Level/Provincial Level
 - B. Preferential Lending:
 - 1. Government Policy Lending Program
 - 2. Loans and Interest Subsidies Related to the Northeast Revitalization Program.
 - 3. Loans Pursuant to the Liaoning Province's Five-Year Framework
- (III) Revenue foregone or not collected which was otherwise due e.g. fiscal incentives such as tax credits
- C. Income Tax Programs Conferred by the Central Government:
 - 1. Preferential Tax Policies for Foreign Invested Enterprises - Two Free, Three Half Program
 - 2. Income Tax Exemption for Export-Oriented FIEs
 - 3. Reduced Income Tax Rates for FIEs Based on Location
 - 4. Corporate Income Tax Refund Program for Reinvestment of FIE Profits in Export-Oriented Enterprises
 - 5. Reduced Income Tax Rate for New or High Technology Enterprises
 - 6. Preferential Tax Policies for Research and Development at FIEs
 - 7. Income Tax Credits on Purchases of Domestically Produced Equipment - Applicable to Domestically Owned Companies
 - 8. Income Tax Credits on Purchases of Domestically Produced Equipment - Applicable to FIEs
- D. Income Tax Programs Adopted by Provincial Governments
- E. Indirect Tax Programs and Import Tariff Programs Conferred by the Central Government
 - 1. VAT Exemption on Exports
 - 2. VAT Rebate for FIE Purchases of Domestically Produced Equipment
 - 3. VAT and Tariff Exemptions on Imported Technology and Equipment for Encouraged Industries

(IV) Provision of goods or services other than general infrastructure

1. Provision of Electricity, Natural Gas, Water and Utilities for Less Than Adequate Remuneration
2. Provision of Land for Less Than Adequate Remuneration

The Pre-initiation consultations were held with the representatives of the Government of China PR on 19th November 2008 in New Delhi. During the consultations, the Govt. of China claimed that a number of schemes/program did not exist or were revoked/modified during the POI. However, the Govt. of China has not established that there was no countervailable subsidy beyond *de-minimis* limits during the POI.

The claims of the Govt. of China have been taken on record and would be further examined during the course of the investigation. There is sufficient evidence with regard to existence of countervailable subsidies to justify initiation of countervailing duty investigation in terms of the Rules.

9. Export Price

The petitioner has claimed export price based on the transaction-wise data provided by IBIS. There is sufficient evidence with regard to export price to justify initiation of countervailing duty investigation in terms of the Rules.

10. Subsidy margin

The petitioner has estimated margin of subsidy in various schemes and has claimed that the Chinese producers have benefited from alleged schemes beyond *de-minimis* limits.

11. Dumping of the goods from China PR

In view of dumping of the subject goods earlier established, the subject goods attract anti dumping duty in case of imports from China PR. Based on a petition separately filed by the domestic industry requesting review of existing anti dumping duty, the Authority has separately initiated a mid-term review investigation vide notification no 15/24/2008-DGAD dated 17th November 2008.

12. Injury and Causal Link

The petitioner has furnished information on various parameters relating to 'injury' to the domestic industry as prescribed under Annexure-I of the Rules. Petitioner has claimed that the domestic industry has suffered continued injury inspite of existing anti dumping duties. The evaluation of the information shows that the volume of imports is significant in absolute terms and in relation to production & consumption in India. Imports are undercutting the prices of the domestic industry. On the basis of the information provided, it is seen that the performance of the domestic industry deteriorated in terms of profits, return on investments, cash profit and inventories on account of alleged subsidization and dumping of subject goods from China PR.

There is sufficient evidence that the 'injury' to the domestic industry has also been caused by subsidized imports from China PR to justify initiation of a countervailing duty investigation in terms of the Rules.

13. Procedure & Submission of information

During the course of the investigation, the Authority will determine whether the product concerned originating in the subject country is being subsidised & countervailable and whether this subsidisation has caused injury to the Indian domestic industry.

In terms of Article 13.2 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, throughout the period of investigation, Government of China PR shall be afforded a reasonable opportunity to continue consultations, with a view to clarifying the factual situation and to arriving at a mutually agreed solution.

The exporters in China PR, Government of China PR, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may write to:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Department of Commerce,
Ministry of Commerce & Industry,
Room No.240, Udyog Bhawan,
New Delhi-110107.

As per Rule 7(5) of the Rules supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the article under investigation, and to representative consumer organizations who can furnish information which is relevant to the investigation regarding subsidy, injury and causal link. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limit set out below.

14. Time limit

Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

15. Submission of Information on Non-Confidential basis

In terms of Rule 8 of the CVD rules, the interested parties are required to submit non-confidential version of any confidential information provided to the Authority. The non-confidential version or non-confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties. If in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summary; a statement of reason thereof is required to be provided.

16. Non cooperation

In terms of Rule 7(8), in case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

17. Inspection of Public File

In terms of Rule 7(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

R. GOPALAN, Designated Authority

